PRICE OF NEWSPRINTS MANUFACTURED IN HIMACHAL FACTORY

5691. SHRI PARTAP SINGH : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether the price of the newsprint to be produced in the proposed newsprint factory in Himachal Pradesh is to be fixed by the Government of India;

(b) whether due to the delay in fixation of the price, the construction of the factory is being delayed; and

(c) if so, the reasons, therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI SIDDHESHWAR PRASAD) : (a) There is no price control on newsprint.

(b) and (c) : Do not arise.

देश में भूमिगत पाकिस्तानी नागरिक

5692. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर इस समय पूरे देश में अनुमानतः राज्यवार कितने पाकिस्तानी नागरिक भूमिगत होकर रह रहे हैं; और

(ख) उनका पता लगाने और उन्हें निकाल बाहर करने के लिए अब तक राज्य सरकारों ने क्या कार्यवाही की है और इस बारे में केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसीन) : (क) अब तक प्राप्त सूचना का एक विवरण संलग्न है। शेष राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायगी।

(ख) तलाश करने के नोटिस जारी करने के अतिरिक्त उनका पता लगाने तथा कानून के अनुसार उनके संबंध में कार्यवाही करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

विवरण

राज्य का नाम	31-3-1972 को भूमिगत पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	310
गुजरात	133
महाराष्ट्र	598
मैसूर	71
नागालैण्ड	कोई नहीं
तमिलनाडु	22
उत्तर प्रदेश	842
अरुणाचल प्रदेश	कोई नहीं
चंडीगढ़	कोई नहीं
दिल्ली	36
गोआ, दमन और दीव	कोई नहीं
लक्कादीव, मिनीकोय और अमिनदीवी द्वीप समूह	कोई नहीं

वैध पारपत्रों पर हरियाणा में आये और भूमिगत हो गये पाकिस्तानी नागरिक

5693. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली जनवरी, 1970 से अब तक हरियाणा में कितने पाकिस्तानी नागरिकों ने वैध पारपत्रों पर भारत आकर जिलावार अपने नाम रजिस्टर कराये; और

(ख) इस अवधि में कितने पाकिस्तानी नागरिकों की वीजा-अवधि बढ़ाई गई; और

(ग) केन्द्रीय और राज्य सरकारों की सूचना के अनुसार इस समय पूरे राज्य में कितने पाकिस्तानी नागरिक भूमिगत हैं और उन्हें ढूंढ कर वापस भेजने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) 1 जनवरी, 1970 से 31 मार्च, 1972 तक की अवधि में उनकी संख्या इस प्रकार थी :—

हिसार	17
रोहतक	40
गुड़गांव	363
करनाल	76
अम्बाला	34
जीन्द	13
महेन्द्रगढ़	6

(ख) : 16

(ग) : कोई नहीं ।

वैध पारपत्रों पर पंजाब में आये पाकिस्तानी नागरिक

5694. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली जनवरी, 1970 से अब तक पंजाब में कितने पाकिस्तानी नागरिकों ने वैध पारपत्रों पर भारत आकर जिलावार अपने नाम रजिस्टर कराये ;

(ख) इस अवधि में कितने पाकिस्तानी नागरिकों की बीजा अवधि बढ़ाई गई; और

(ग) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की सूचना के अनुसार इस समय पूरे राज्य में कितने पाकिस्तानी नागरिक भूमिगत हैं और सरकार ने उन्हें ढूंढ कर वापस भेजने के लिये क्या कदम उठाये है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

राजस्थान के जिला बाड़मेर सहकारी बैंक से भारी रकम लेकर पाकिस्तान भाग जाने वाले व्यक्ति

5695. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या गृह मंत्री राजस्थान के जिला बाड़मेर सहकारी बैंक से भारी रकम लेकर पाकिस्तान भाग जाने वाले व्यक्तियों के बारे में, नवम्बर 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 456 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार से अपेक्षित सूचना इस बीच एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य-मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि उन्हे बाड़मेर जिला सहकारी बैंक से 2 लाख रुपये की रकम ऋण लेने के पश्चात् पाकिस्तान भाग जाने वाले 413 व्यक्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है । किन्तु 24 सहकारी समितियो के 390 सदस्य जो पाकिस्तान को चले गए थे, के नाम में 38,400/- रुपये का ऋण बकाया था । इस रकम में से 19,000/- रुपये जमानतियों से वसूल कर लिये गये है और शेष रकम जमानतियों से वसूल करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

पुलिस बल का आधुनिकीकरण करने के लिए मध्य प्रदेश को धन का आवंटन

5696. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस कर्मचारियों के आवास की सुविधाओं की व्यवस्था और पुलिस बल का आधुनिकीकरण करने के लिए राज्यों की वित्तीय सहायता योजना के अन्तर्गत वर्ष 1972-73 में मध्य प्रदेश को कितनी राशि आवंटित की गई है अथवा करने का विचार है ?